



UP - PCS

प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा

Prelims & Mains

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज

सामान्य अध्ययन

पेपर 3 – भाग 1

भारतीय अर्थव्यवस्था



UP - PCS

पेपर - 3 भाग - 1

भारतीय अर्थव्यवस्था

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	राष्ट्रीय आय <ul style="list-style-type: none">राष्ट्रीय आय के पहलूराष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीकेआर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति	1
2.	धन और पैसे की आपूर्ति <ul style="list-style-type: none">धन का विकासधन के कार्यधन का वर्गीकरणधन के प्रकारक्रिप्टोकॉर्सेसी और बिटकॉइनमुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक समुच्चय	7
3.	मुद्रास्फीति और आर्थिक पुनः प्राप्ति <ul style="list-style-type: none">मुद्रास्फीति के कारणमुद्रास्फीति के प्रकारWPI बनाम CPIउत्पादक मूल्य सूचकांक(PPI)आवास मूल्य सूचकांकसेवा मूल्य सूचकांक (SPI)मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरणमुद्रास्फीति के प्रभावआर्थिक सुधारआर्थिक सुधार का आकार	15
4.	भारत में बैंकिंग <ul style="list-style-type: none">वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरणभारतीय रिजर्व बैंक (RBI)दिवाला और दिवालियापनसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुषवित्तीय समावेशन	25
5.	वित्तीय प्रणाली <ul style="list-style-type: none">मुद्रा बाजारवित्तीय विनियमन	44
6.	मौद्रिक नीति <ul style="list-style-type: none">मात्रात्मक उपकरणगुणात्मक उपकरणमौद्रिक नीति समिति	53

7.	बाहरी क्षेत्र और भुगतान संतुलन <ul style="list-style-type: none"> • महत्वपूर्ण परिभाषाएं • भुगतान का संतुलन • मुद्रा प्रकार • विदेशी निवेश • बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) • व्यापार संवर्धन • निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं • विदेश व्यापार नीति के तहत प्रमुख पहल • नई विदेश व्यापार नीति 2021-2026 • बैंकिंग पूंजी लेनदेन • मुद्रा परिवर्तनीयता • विदेशी कर्ज • भारत में विनिमय दर प्रबंधन • व्यापार संतुलन 	60
8.	भारतीय सार्वजनिक वित्त <ul style="list-style-type: none"> • सार्वजनिक राजस्व • सरकारी व्यय • सार्वजनिक ऋण • राजकोषीय नीति • राजकोषीय नीति बनाम मौद्रिक नीति • घाटा • राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपाय • सार्वजनिक ऋण 	78
9.	बजट बनाना <ul style="list-style-type: none"> • वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) • बजट के अधिनियमन की प्रक्रिया • कोविड टीकाकरण : वित्त वर्ष 22 में ₹35000 करोड़ खर्च करना। • भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा: • सरकारी खाते • घाटा वित्तपोषण 	89
10.	कराधान <ul style="list-style-type: none"> • कराधान के पीछे उद्देश्य • कराधान के तरीके • कर के प्रकार • कर सुधार • राजा चेलिया समिति (1990 के दशक के प्रारंभ में) • कराधान में महत्वपूर्ण शर्तें 	96
11.	कृषि <ul style="list-style-type: none"> • पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि का विकास • कृषि एवं हरित क्रांति • भूमि उपयोग से संबंधित शर्तें • भूमि उपयोग से संबंधित शर्तें 	114

	<ul style="list-style-type: none"> • कृषि विपणन • सार्वजनिक वितरण प्रणाली • निवेश प्रबंधन योजनाएं/मिशन • जल प्रबंधन-सूक्ष्म सिंचाई • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम • कृषि साख • खाद्य सुरक्षा • उत्पादन प्रबंधन योजनाएं • न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) • प्रधानमंत्री आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) • उत्पादन प्रबंधन योजनाएँ • आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 • कृषि निर्यात नीति 2018 • मूल्य स्थिरीकरण के उपाय • कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर • कृषि में विस्तार प्रबंधन • कृषि विस्तार के लिए जनसंचार माध्यमों का समर्थन • संबद्ध गतिविधियों का प्रबंधन-अतिरिक्त आय अर्जित करना 	
12.	अनुदान <ul style="list-style-type: none"> • कृषि अनुदान की आवश्यकता • अनुदानों का वर्गीकरण • संवितरण के विभिन्न तरीके • भारतीय खाद्य निगम (FCI) • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 • विश्व व्यापार संगठन और कृषि अनुदान 	146
13.	आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण <ul style="list-style-type: none"> • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) • आपूर्ति श्रृंखला योजनाएं • आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) 	152
14.	बुनियादी ढाँचा <ul style="list-style-type: none"> • अवसंरचना विकास • उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना। • व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) • सड़कें • भारतमाला परियोजना • रेलवे • बंदरगाह • हवाई अड्डे • औद्योगिक गलियारे • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) • मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क 	159

	<ul style="list-style-type: none"> • इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 17, ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित जोगीघोपा जलमार्ग टर्मिनल, नवनिर्मित रूपसी और गुवाहाटी हवाई अड्डों के साथ-साथ मुख्य रेलवे मार्ग से सीधा संपर्क होगा। • बिजली क्षेत्र • तेल और गैस क्षेत्र • ऊर्जा सुरक्षा • जैव ईंधन • स्मार्ट सिटी, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) और सभी के लिए आवास • सभी के लिए आवास • एनआईआईएफ (राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष) • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 	
15.	उद्योग <ul style="list-style-type: none"> • 1991 से पहले की औद्योगिक नीति • औद्योगिक नीति संकल्प, 1948 • औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 • नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न • औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1977 • औद्योगिक नीति वक्तव्य, 1980 • 1991 के बाद की औद्योगिक नीति • उद्योग पर LPG सुधारों का प्रभाव • राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 • विनिवेश के प्रकार • व्यापार सुगमता • औद्योगिक विकास के चरण • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) • सीमित देयता भागीदारी (LLP) अधिनियम, 2008: • खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) • क्षेत्रीय चिंताएं • स्टार्ट-अप इंडिया 	180
16.	भारत में भूमि सुधार <ul style="list-style-type: none"> • भूमि सुधार के लिए तर्क • भूमि सुधार के घटक • भूमि सुधारों का प्रभाव • भूमि सुधार [स्वतंत्रता से पहले और बाद में] • भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 • भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में समस्याएं • सामाजिक प्रभाव आकलन 	198
17.	आर्थिक सुधार <ul style="list-style-type: none"> • 1991 आर्थिक संकट • 1991 के सुधार • भारत में आर्थिक सुधार • सुधार के उपाय • आर्थिक सुधारों की पीढ़ी • मिश्रित अर्थव्यवस्था 	207

18.	भारत में योजना <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय योजना • राष्ट्रीय योजना • योजना के प्रकार • योजना के प्रमुख उद्देश्य • भारत में योजना का विकास • राष्ट्रीय विकास परिषद • पंचवर्षीय योजनाएं • NITI (नीति) आयोग 	215
19.	भारत में बेरोजगारी <ul style="list-style-type: none"> • भारत में बेरोजगारी का उपाय • भारत में बेरोजगारी के प्रकार • भारत में बेरोजगारी के कारण • बेरोजगारी का प्रभाव • सरकार की पहल 	226
20.	गरीबी <ul style="list-style-type: none"> • गरीबी के प्रकार • भारत में गरीबी का आकलन • गरीबी के आकलन के लिए विभिन्न समितियों की अनुशंसाएं • रंगराजन समिति • भारत में गरीबी के कारण • भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम • बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 	232
21.	समावेशी विकास <ul style="list-style-type: none"> • आर्थिक संवृद्धि • आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक • आर्थिक विकास • असमानता • सांख्यिकी • खुशहाली • समावेशी वृद्धि और संबंधित मुद्दे • भारत में निर्धनता आकलन • जनसांख्यिकीय विभाजन • सतत विकास लक्ष्य (SDGs) • सतत विकास के तत्व 	238
22.	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान <ul style="list-style-type: none"> • ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष • विश्व बैंक • अन्य वस्तु व्यापार समझौते • भारत और विश्व व्यापार संगठन • एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक • एशियाई विकास बैंक • आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) 	249



- **राष्ट्रीय आय:** मूल्यहास को समायोजित करने के बाद, एक लेखा वर्ष के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
 - यह कारक लागत (FC) पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) है।
 - इसमें कर, मूल्यहास और गैर-कारक इनपुट (कच्चा माल) शामिल नहीं है।
- देश की प्रगति के निर्धारण में भी उपयोगी है।
- इसमें निहित हैं: मजदूरी, ब्याज, किराया और उत्पादन के घटकों द्वारा प्राप्त लाभ जैसे: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता।
- **घरेलू आय:** मूल्यहास को समायोजित करने के बाद, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
 - यह कारक लागत पर एनडीपी (NDP) है।
- एनएनपी (NNP) और एनडीपी (NDP) दोनों को स्थिर कीमतों (वास्तविक आय) या बाजार मूल्य (नाममात्र आय) पर मापा जा सकता है।
- **राष्ट्रीय आय:** घरेलू आय + एनएफआई

कुछ महत्वपूर्ण शर्तें

कारक लागत(FC)	<ul style="list-style-type: none"> ● किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या उपयोग किए गए उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत।
मूल कीमत(BP)	<ul style="list-style-type: none"> ● जब किसी सेवा या वस्तु के उत्पादन के कारक लागत में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाए जाने वाले सभी करों को जोड़कर उसमें से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली सभी सब्सिडियों को घटाया जाता है तब प्राप्त मूल्य मूल कीमत कहलाता है। ● $\text{मूल कीमत(BP)} = \text{कारक लागत(FC)} + \text{उत्पादन कर(PT)} - \text{उत्पादन सब्सिडी(PS)}$
बाजार मूल्य(MP)	<ul style="list-style-type: none"> ● जिस कीमत पर कोई वस्तु बाजार में बेची जाती है। इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज, इनपुट मूल्य, लाभ और उत्पादन की अन्य लागतें निहित हैं। ● सरकार द्वारा लगाए गए कर और सरकार द्वारा प्रदान की गई उत्पादन सब्सिडी भी निहित है। ● $\text{बाजार मूल्य(MP)} = \text{मूल कीमत(BP)} + \text{उत्पाद कर(PT)} - \text{उत्पाद सब्सिडी(PS)}$ या $\text{बाजार मूल्य(MP)} = \text{कारक लागत(FC)} + \text{शुद्ध अप्रत्यक्ष कर(NIT)}$
मूल्यहास	<ul style="list-style-type: none"> ● मूल्यहास का अर्थ पूंजीगत संपत्ति के मूल्य में समय के अनुसार आने वाली कमी से है। मूल्यहास के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे- <ul style="list-style-type: none"> - सम्पत्ति का पुराना हो जाना (मशीनरी/फर्नीचर) - उसका प्रचलन से बाहर हो जाना - तकनीकी में बदलाव आना / अपग्रेड होना
स्थानान्तरण भुगतान	<ul style="list-style-type: none"> ● एक मौद्रिक भुगतान जिसके लिए कोई वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है।

- स्थानीय, राज्य और संघीय सरकारों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को धन के पुनर्वितरण के प्रयासों को आमतौर पर हस्तांतरण भुगतान के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी बीमा जैसे हस्तांतरण भुगतान संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हैं।
- स्थानांतरण भुगतान का उपयोग आमतौर पर कॉर्पोरेट, राहत पैकेज और सब्सिडी का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है।

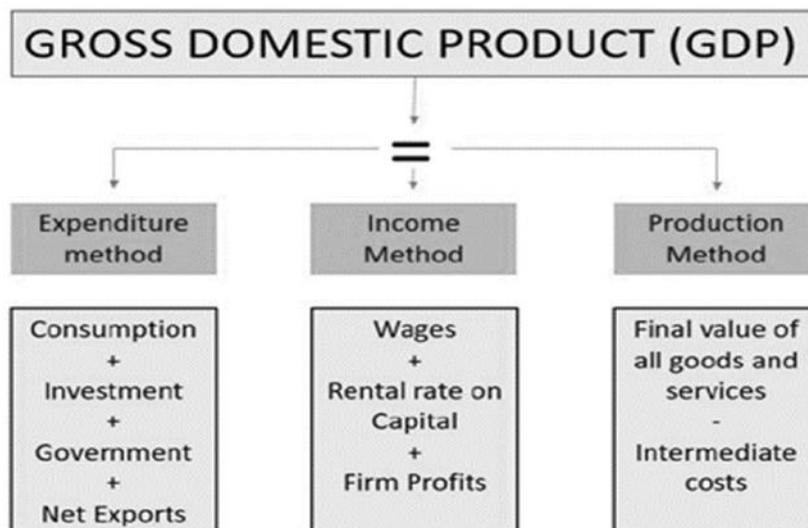
राष्ट्रीय आय के पहलू

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

- किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- आर्थिक संकेतक किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- नियमित अवधियों पर अनुमानित (जैसे- त्रैमासिक / वार्षिक)
 - भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उत्पादन क्षेत्र में शामिल हैं-
 - किसी देश की भौगोलिक सीमाएँ जिसमें उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) शामिल हैं। (200 समुद्री मील या 360 किलोमीटर तक)
 - विभिन्न देशों में एक देश का दूतावास
 - वाहन जैसे जहाज, विमान आदि जिस देश में पंजीकृत होते हैं, वे उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत माने जाते हैं।
- उत्पाद में निहित हैं: देश के घरेलू क्षेत्र में सामान्य निवासियों और अनिवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ।
 - विदेश से शुद्ध कारक आय (NFIA) शामिल नहीं है।
- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा गणना की जाती है।
- 'मात्रात्मक अवधारणा' और अर्थव्यवस्था की आंतरिक ताकत को इंगित करता है।
- आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा सदस्य की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

जीडीपी = खपत + निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात - आयात

सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए तरीके:



सांकेतिक जीडीपी	वास्तविक जीडीपी
<ul style="list-style-type: none"> देश के भीतर उत्पादित कुल वित्तीय व्यवसाय मूल्य। मुद्रास्फीति के बिना समायोजित। चालू वर्ष की कीमतों पर। उच्च मूल्य एक वर्ष की तिमाहियों की तुलना करता है। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद = चालू वर्ष में उत्पादन * चालू वर्ष में मूल्य</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> जीडीपी मीट्रिक समायोजित : सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के साथ। मुद्रास्फीति से समायोजित नियमित कीमतों पर कम मूल्य दो या दो से अधिक वित्तीय वर्ष की तुलना करता है। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>वास्तविक जीडीपी = चालू वर्ष में उत्पादन * आधार वर्ष मूल्य</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> केवल वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन के आँकड़े सम्मिलित किये जाते हैं।

जीडीपी अपस्फीतिकारक (GDP Deflator)

- उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है।
- मुद्रास्फीति माप संकेतक है जो CPI सूचकांक की तुलना में अधिक व्यापक है।

जीडीपी डिफ्लेटर = सांकेतिक जीडीपी / वास्तविक जीडीपी

जीडीपी विकास दर:

- मापता है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है।
- जीडीपी में लगातार दो वर्षों या तिमाहियों में परिवर्तन को मापता है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर = $100 \times [(जीडीपी\ चालू\ वर्ष/तिमाही - जीडीपी\ पिछला\ वर्ष/तिमाही) / जीडीपी\ पिछला\ वर्ष/तिमाही]$

- वास्तविक आर्थिक विकास दर क्रय शक्ति को ध्यान में रखती है और इसमें मुद्रास्फीति-समायोजित होती है।

कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपीएफसी)

- कारक लागत एक वस्तु के उत्पादन की लागत है। इसमें भूमि, श्रम, पूँजी और उत्पादक के मुनाफे की लागत शामिल होती है।

बाजार मूल्य पर जीडीपी (GDPMP)

- बाजार मूल्य में साधन लागत के साथ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। (शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कुल अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का अंतर)

GDPMP = GDPFC + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

सकल मूल्य वर्धित (GVA)

- इसमें GDP की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न चरणोंको शामिल किया जाता है।
- इसमें दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं के आधार पर गणना की जाती है।

GVA = GDP + सब्सिडी - कर

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP)

- किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर सृजित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल संपत्ति।
- राष्ट्रीय पूंजी परिसंपत्तियों जैसे मशीनरी, घरों और कारों के मूल्यहास का मूल्य एनडीपी की गणना के लिए जीडीपी से घटाया जाता है।
- अन्य कारण: परिसंपत्ति का अप्रचलन और पूर्ण विनाश को भी एनडीपी द्वारा ध्यान में रखा जाता है।



शुद्ध घरेलू उत्पाद(NDP) =सकल घरेलू उत्पाद(GDP) –मूल्यहास.

• महत्व

- अर्थव्यवस्था को मूल्यहास के कारण हुए नुकसान की ऐतिहासिक स्थिति को समझना।
- तुलनात्मक अवधि में उद्योग और व्यापार में मूल्यहास की क्षेत्रीय स्थिति को समझना और विश्लेषण करना।
- आर और डी के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक समय अवधि में मूल्यहास के स्तर को ठीक करने का प्रयास किया है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- किसी देश में नागरिकों और उद्यमों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, चाहे वे कहीं भी उत्पादित हों।
- यह विदेशों से अपनी आय के साथ जोड़ा गया देश का सकल घरेलू उत्पाद है।
- 'विदेश से आय' में निम्नलिखित शामिल हैं :
 - व्यापार संतुलन: किसी देश के कुल निर्यात और आयात का वर्ष के अंत में शुद्ध परिणाम।
 - बाहरी ऋणों पर ब्याज: देश द्वारा उधार दिए गए धन पर ब्याज की शेष राशि और उस धन पर ब्याज जो उसने अन्य देशों से उधार लिया है।
 - भारत हमेशा विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक 'शुद्ध ऋणी' रहा है।
 - निजी प्रेषण: विदेशों में काम कर रहे भारतीयों (भारत में) और भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिकों (अपने गृह देशों में) द्वारा 'निजी हस्तांतरण' का खाता।



GNP(Y) = उपभोग व्यय (सी) + निवेश (आई) + सरकारी व्यय (जी) + शुद्ध निर्यात (एक्स) + विदेश से शुद्ध आय (Z).

• Y = C + I + G + X + Z

- जीएनपी के कारक: उपकरण, मशीनरी, कृषि उत्पादों और करों और कुछ सेवाओं जैसे परामर्श, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी वस्तुओं का निर्माण।
- सेवाओं को वितरित करने की लागत की गणना नहीं की जाती है।
- जब कोई नागरिक दोहरी नागरिकता रखता है तो प्रति व्यक्ति जीएनपी का उपयोग देश-दर-देश के आधार पर जीएनपी की गणना के लिए किया जाता है।
- उस स्थिति में, उनकी आय को प्रत्येक देश के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में दो बार गिना जाता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यहास को हटाकर प्राप्त मूल्य NNP कहलाता है।
- यह निर्धारित करता है कि एक देश एक विशिष्ट समय अवधि में कितना उपभोग कर सकता है।



NNP = GNP –मूल्यहास
 or
NNP = GDP + विदेशों से आय - मूल्यहास

- जब किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) गिरता है,
 - व्यवसाय उन उद्योगों में स्थानांतरित होने पर विचार करते हैं जिन्हें मंदी-अभेद्य माना जाता है।

निजी आय (PI)	<ul style="list-style-type: none"> ● किसी देश के नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से अर्जित की गई धन राशि। ● जैसे रोजगार से प्राप्त धन, निवेश द्वारा भुगतान लाभांश और वितरण, संपत्ति के स्वामित्व से प्राप्त किराया, और उद्यमों से लाभ साझा करना। ● अधिकांश मामलों में व्यक्तिगत आय पर कराधान लगाया जाता है। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> $PI = \text{राष्ट्रीय आय} - \text{अविभाजित लाभ} - \text{परिवारों द्वारा प्रदत्त शुद्ध ब्याज} - \text{कॉर्पोरेट टैक्स} + \text{सरकार और फर्मों से परिवारों को भुगतान हस्तांतरण}$ </div>
व्यक्तिगत प्रयोज्य आय (PDI)	<ul style="list-style-type: none"> ● परिवारों के लिए उपलब्ध आय जिसे वे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। ● करों के भुगतान और अन्य गैर-कर भुगतान के बाद उपलब्ध आय। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> $PDI = PI - \text{निजी कर भुगतान} - \text{गैर-कर भुगतान}$ </div>
राष्ट्रीय डिस्पोजेबल आय	<ul style="list-style-type: none"> ● संस्थागत क्षेत्रों की सकल (या शुद्ध) प्रयोज्य आय का योग। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> $\text{सकल (या शुद्ध) एनडीआई} = \text{सकल (या शुद्ध) राष्ट्रीय आय (बाजार कीमतों पर)} - \text{अनिवासी इकाइयों को देय वर्तमान स्थानान्तरण}$ </div>

राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके



आय विधि	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वरोजगार द्वारा सभी उत्पादन कारकों (किराया, वेतन, ब्याज, लाभ) और मिश्रित-आय को जोड़कर अनुमानित। ● हम इस प्रक्रिया का उपयोग करके किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त सभी शुद्ध आय भुगतान को जोड़ते हैं। ● उत्पादन के सभी कारकों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। <ul style="list-style-type: none"> ○ उदाहरण: शुद्ध किराया, मजदूरी, ब्याज, और मुनाफा। ● हस्तांतरण भुगतान के रूप में प्राप्त आय इसमें शामिल नहीं की जाती। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> $\text{शुद्ध राष्ट्रीय आय} = \text{कर्मचारियों का मुआवजा} + \text{मिश्रित परिचालन अधिशेष (W + R + P + I)} + \text{शुद्ध आय} + \text{विदेश से शुद्ध कारक आय}$ <p>जहाँ,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ W = Wages and salaries ■ R = Rental Income ■ P = Profit ■ I = Mixed Income </div>
उत्पाद/मूल्य वर्धित विधि	<ul style="list-style-type: none"> ● एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में बाजार कीमतों पर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ● जीएनपी की गणना करने के लिए, <ul style="list-style-type: none"> ○ सभी उत्पादक गतिविधियों से डेटा एकत्र किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। इसमें

	<p>निम्नलिखित शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ कृषि माल, ■ खनिज, और ■ औद्योगिक उत्पादों ■ परिवहन, बीमा, संचार, वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों आदि द्वारा किए गए उत्पादन में योगदान। <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>राष्ट्रीय आय = जीएनपी - पूंजी की लागत - मूल्यहास - अप्रत्यक्ष कर</p> </div>
व्यय विधि	<ul style="list-style-type: none"> ● राष्ट्रीय आय को व्यय प्रवाह के रूप में मापा जाता है। ● इसमें समाज द्वारा कुल व्यय का योग शामिल है : <ul style="list-style-type: none"> ○ निजी उपभोग व्यय, ○ शुद्ध घरेलू निवेश, ○ वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च, और ○ शुद्ध विदेशी निवेश। <p>राष्ट्रीय आय = राष्ट्रीय उत्पाद = राष्ट्रीय व्यय</p>

आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति

- **गठन:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा।
- **अध्यक्ष:** पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद्
- **कार्य**
 - विश्लेषण और विकास : रोजगार, उद्योग और सेवाओं पर देश का सर्वेक्षण
 - डेटा स्रोतों, संकेतकों और परिभाषाओं के वर्तमान ढांचे को देखना
 - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, समय-समय पर श्रम बल सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों के लिए।
 - 4 स्थायी समितियों श्रम बल सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, सेवा क्षेत्र, और अनिगमित क्षेत्र की फर्मों को SCES में समाहित किया जाएगा।
 - 108 अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत में सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रभावित करने में "राजनीतिक भागीदारी" पर चिंता व्यक्त की।
 - सांख्यिकीय संगठनों की "संस्थागत स्वतंत्रता" और अखंडता को बहाल करने की अपील की।



2

CHAPTER

धन और पैसे की आपूर्ति



धन का विकास



वस्तु विनिमय प्रणाली	<p>मुद्रा की मध्यस्थता से वस्तुओं का विनिमय</p> <ul style="list-style-type: none"> • धन और बैंकिंग की कोई अवधारणा नहीं होती।
धन की अवधारणा	<p>"मुद्रा विनिमय का सबसे आम तौर पर स्वीकृत माध्यम है":</p> <ul style="list-style-type: none"> • भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार की जाने वाली कोई वस्तु जैसे मुद्रा, सिक्के आदि। • पैसा केवल एक सुविधा के रूप में कार्य करता है, अन्यथा आवश्यकता नहीं होती

धन के कार्य



विनिमय की इकाई	<ul style="list-style-type: none"> • सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापने के लिए। • मूल्य में व्यक्त (मौद्रिक मूल्य / अच्छी सेवा की इकाई)। • उदाहरण: भारत में एक वस्तु की प्रति इकाई रुपये है (किलोग्राम, लीटर आदि)
विनिमय का माध्यम	<ul style="list-style-type: none"> • वह वस्तु जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। • यह चयन की आजादी को इंगित करता है जिसमें वस्तु या सेवा में से किसी भी का उपयोग किया जा सकता है। • यह फ़ंक्शन ठीक से उपलब्ध है यदि पैसे का मूल्य स्थिर रहता है।
आस्थगित भुगतानों के मानक	<ul style="list-style-type: none"> • भावी भुगतानों के आस्थगन के लिए। • उदा. पेंशन सिद्धांत और ऋण पर ब्याज, वेतन आदि।
मूल्य संचय	<ul style="list-style-type: none"> • इसमें उत्पादों और सेवाओं को बाद में रखा या आदान-प्रदान किया जा सकता है। • धन धारकों के पास क्रय शक्ति की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। • उदाहरण: बांड, संपत्ति और घर सभी पैसे के समान उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

धन का वर्गीकरण



पूर्ण धन

- मुद्रा जिसका मूल्य गैर-मौद्रिक उद्देश्यों के लिए एक वस्तु के रूप में उसके अंकित मूल्य जितना ही महत्वपूर्ण है।
- उदा. सोना, चांदी, मवेशी आदि।

पूर्ण धन प्रतिनिधि

- एक प्रकार का धन जो कागज से बनता है।
- लाभ- व्यापार में शामिल होने के लिए सुविधाजनक है जिसके लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है।

साख मुद्रा



- धन जिसका मूल्य उस सामग्री के वस्तु मूल्य से अधिक है जिससे धन बनाया जाता है।

धन के प्रकार

आरक्षित पैसा	<ul style="list-style-type: none"> • आरबीआई की मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। • आरबीआई : रुपये के मूल्यवर्ग में मुद्रा नोट जारी करता है। 2, 5, 10, 20, 50, 100 और 2000 रुपये। • भारतीय रिजर्व बैंक (भारत सरकार की ओर से) : <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 रुपये के नोट और सिक्कों और छोटे मूल्यवर्ग के सिक्के के रूप में मुद्रा जारी करता है। <p>रिजर्व मनी 6 प्रकार की होती है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • सरकार को आरबीआई का शुद्ध ऋण। • बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण। • वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण। • भारतीय रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार। • जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं। • भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध गैर-मौद्रिक देनदारियां।
संकीर्ण धन	<ul style="list-style-type: none"> • सभी भौतिक धन, जैसे सिक्के और नकद, साथ ही मांग जमा और आरबीआई द्वारा आयोजित अन्य तरल संपत्ति। • नैरो मनी (M1) करेंसी + लोगों के पास बैंक मनी। • यह बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक सावधि जमा को बाहर करता है <ul style="list-style-type: none"> ○ ये आय-उत्पादक परिसंपत्तियां हैं और इसलिए तरल नहीं हैं।
धन के पास	<ul style="list-style-type: none"> • कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां, जैसे कि करेंसी नोट और चेक योग्य जमा, तरल के रूप में नहीं हो सकती हैं। • उदा. : सावधि जमा, बैंकों की स्वीकृति, विनिमय के बिल, सरकारी और निजी बांड, बचत प्रमाणपत्र, शेयर और अन्य वित्तीय साधन • धन की शक्ति है लेकिन इसमें तत्काल आर्थिक गतिविधियों को करने में असमर्थ हैं। • अत्यधिक तरल (आसानी से पैसे में परिवर्तित किया जा सकता है)। • जैसे: <ul style="list-style-type: none"> ○ बचत खाता, ○ धन निधि, ○ बैंक सावधि जमा (जमा प्रमाणपत्र), ○ सरकारी खजाना प्रतिभूतियां (जैसे टी-बिल), ○ उनकी मोचन तिथि के निकट बांड, ○ विदेशी मुद्राएं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो या येन।
कठिन पैसा	<ul style="list-style-type: none"> • सोने या अन्य अत्यंत विश्वसनीय संपत्तियों के समर्थन से जारी किया गया धन। • कठिन पैसा मुद्रास्फीति के जोखिम से बचाता है।
शीतल धन	<ul style="list-style-type: none"> • सरकारी बांडों द्वारा समर्थित कागजी मुद्रा। • नए पैसे के अनुपात में सोने की तरह पर्याप्त भंडार के बिना मुद्रित धन • सॉफ्ट मनी के तहत मुद्रास्फीति का एक मजबूत तत्व है।
फिएट मनी	<ul style="list-style-type: none"> • फिएट मनी बैंकनोट्स और सिक्कों को संदर्भित करता है। • उनके पास सोने या चांदी के सिक्के के समान अंतर्निहित मूल्य नहीं है।

	<ul style="list-style-type: none"> यानी कानूनी निविदाएं, <ul style="list-style-type: none"> कोई भी नागरिक उन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार करने से इंकार नहीं कर सकता।
चलायमान मुद्रा	<ul style="list-style-type: none"> फंड : देश की अनुकूल ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए किसी देश में प्रवाहित होना। प्राप्तकर्ता देश के भुगतान संतुलन पर प्रभाव डालते हैं और विनिमय दर को बढ़ाते हैं।
कानूनी निविदा पैसा	<ul style="list-style-type: none"> 1934 का आरबीआई अधिनियम: बैंक नोट बनाने के लिए आरबीआई को एकमात्र अधिकार प्रदान करता है। करेंसी नोटों के लिए कानूनी निविदा अनंत है। जब कानूनी रूप से देश भर में सभी ऋणों और लेनदेन के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, तो इसे "कानूनी निविदा" कहा जाता है।

- **मुद्राकरण:** किसी चीज़ को धन में बदलने की प्रक्रिया।
 - बैंकिंग में: किसी भी चीज़ को कानूनी निविदा में बदलने या स्थापित करने की प्रक्रिया।
- **विमुद्राकरण:** विमुद्राकरण एक मौद्रिक इकाई की कानूनी निविदा स्थिति को हटाने की प्रक्रिया है।
 - मुद्रा के वर्तमान स्वरूप या रूपों को प्रचलन से हटा लिया जाता है और उन्हें नए नोटों या सिक्कों से बदल दिया जाता है।

क्रिप्टोकॉरेंसी और बिटकॉइन

- डिजिटल या आभासी मुद्रा का प्रकार जो लेनदेन के माध्यम के रूप में कार्य करता है।
- एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है और भौतिक रूप में मौजूद नहीं है (जैसे कागजी धन)
- **बिटकॉइन:** पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकॉरेंसी, 2009 में ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गई।
- अन्य लोकप्रिय क्रिप्टोकॉरेंसी: एथेरियम, रिपल, एनईओ, लिटकोइन, बिटकॉइन केश, लिब्रा, बिनेंस कॉइन आदि।



सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा

- भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा को शामिल करने के लिए "बैंक नोट" की परिभाषा को व्यापक बनाने की सिफारिश की।
- **सीबीडीसी:** फिएट मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण जिसे ब्लॉकचैन-समर्थित वॉलेट के माध्यम से आदान-प्रदान किया जा सकता है और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल प्रकार का कानूनी धन।
- बिटकॉइन पर आधारित है, लेकिन यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से अलग है, जो सरकार द्वारा नहीं बनाई गई हैं और "कानूनी निविदा" नहीं हैं।
- **फिएट मनी:** सरकार द्वारा जारी मुद्रा जो सोने जैसी कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं है
- केंद्रीय बैंकों की अर्थव्यवस्था पर अधिक शक्ति होती है क्योंकि वे यह नियंत्रित कर सकते हैं कि फिएट मनी का उपयोग करके कितना पैसा बनाया जा सकता है।

आवश्यकता

- **कदाचार को संबोधित करना:** आरबीआई डिजिटल धन को विनियमित करके कदाचार को नियंत्रित कर सकता है।
- **अस्थिरता को संबोधित करना:** चूंकि क्रिप्टोकॉरेंसी का मूल्य पूरी तरह से अटकलों (मांग और आपूर्ति) द्वारा निर्धारित किया जाता है, इस प्रकार यह अत्यंत अस्थिर हो जाता है।
- **डिजिटल मुद्रा प्रॉक्सी युद्ध:** डिजिटल युग में, अपरिहार्य प्रॉक्सी युद्ध के खिलाफ पीछे धकेलने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय और वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
- **डॉलर पर निर्भरता कम करना:** भारत को अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ वाणिज्य के लिए एक बेहतर मुद्रा के रूप में डिजिटल रुपया बनाने की क्षमता देता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो जाती है।

- **निजी मुद्रा का आगमन:** यदि निजी मुद्राओं को स्वीकृति मिल जाती है, तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राओं को खतरा होने की संभावना है।

महत्व

- इंटरबैंक सेटलमेंट की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय के भुगतान की अनुमति देते हुए मुद्रा रखरखाव की लागत कम की जा सकती है।
- कागजी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी कम किया जा सकता है।
- यह निजी आभासी मुद्रा के उपयोग से होने वाले सार्वजनिक नुकसान को भी कम करेगा।
- यह उपयोगकर्ताओं को किसी तीसरे पक्ष या बैंक की भागीदारी के बिना घरेलू और सीमा पार लेनदेन निष्पादित करने की अनुमति देगा।
- इसमें प्रमुख लाभ देने की क्षमता है, जैसे कि मुद्रा पर कम निर्भरता, कम लेन-देन की लागत के कारण बढ़ी हुई फौजदारी और कम निपटान जोखिम।
- यह एक अधिक स्थिर, विश्वसनीय, भरोसेमंद, विनियमित और कानूनी निविदा आधारित भुगतान पद्धति को भी जन्म दे सकता है।

मुद्दे

- **आरबीआई की जांच में समस्या:** सीबीडीसी का दायरा, अंतर्निहित तकनीक, सत्यापन प्रक्रिया और वितरण कला।
- कानूनी समायोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि आरबीआई अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों को नकदी के साथ भौतिक रूप में दिमाग में डिजाइन किया गया था।
- **संशोधन आवश्यक:** सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम।
- चिंता का एक अन्य स्रोत तनाव की अवधि के दौरान बैंक से अचानक धन की निकासी है।

हालिया विकास

- **अल साल्वाडोर:** बिटकॉइन को कानूनी नकदी के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश।
- **यूनाइटेड किंगडम:** एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (ब्रिटकोइन) स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है।
- **चीन:** 2020 में अनौपचारिक रूप से "डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डीसी / ईपी" नामक अपने आधिकारिक डिजिटल रुपये का परीक्षण।
- धोखाधड़ी में डिजिटल मुद्राओं का उपयोग किए जाने के बाद, आरबीआई ने अप्रैल 2018 में बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो लेनदेन का समर्थन करने से प्रतिबंधित कर दिया। मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध को गैरकानूनी घोषित किया गया था।

आगे का रास्ता

- भारत अपने नागरिकों को हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल रुपये का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने और एक अप्रचलित बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाने में सक्षम होगा।
- नीति निर्माताओं को मैक्रोइकॉनॉमी और लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम और मनी मार्केट पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, भारत में डिजिटल रुपये की क्षमता का ठीक से आकलन करना चाहिए।

मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक समुच्चय

मुद्रा बाजार

- वित्तीय संगठनों का एक समूह जो अल्पकालिक प्रतिभूतियों, ऋणों, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का व्यापार करता है।
- एक दिन से लेकर एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली वित्तीय आस्तियों में ट्रेड करता है।
- वाणिज्यिक बैंक प्राथमिक साहूकार हैं
- प्रभारी: आरबीआई।



भारत में मुद्रा बाजार के घटक



संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
<ul style="list-style-type: none"> • कॉल और सूचना मुद्रा बाजार • ट्रेजरी बिल बाजार • वाणिज्यिक बिल बाजार • जमा प्रमाणपत्र के लिए बाजार (सीडी) • वाणिज्यिक पत्रों के लिए बाजार (सीपी) • रेपो बाजार • मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड (एमएमएमएफ) • डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया (DFHI) 	<ul style="list-style-type: none"> • स्वदेशी बैंकर • साहूकार • अनियमित गैर-बैंक वित्तीय बिचौलिये (चिट फंड, निधि और ऋणदाता कंपनियां) • वित्त दलाल

संगठित क्षेत्र

कॉल और सूचना मुद्रा बाजार	<ul style="list-style-type: none"> • एक दिवसीय ऋण, उर्फ कॉल ऋण या कॉल मनी के सौदे, एक प्रकार के अल्पकालिक ऋण हैं। • बैंक उधार देना और उधार लेना, दोनों में मुख्य प्रतिभागी हैं।
ट्रेजरी बिल बाजार	<ul style="list-style-type: none"> • केंद्र सरकार की अल्पकालिक देयता। • 2 प्रकार <ul style="list-style-type: none"> ○ साधारण ट्रेजरी बिल: राज्य सरकारों, अर्ध-सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं को निवेश आउटलेट प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। ○ तदर्थ ट्रेजरी बिल: निवेश आउटलेट प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं: <ul style="list-style-type: none"> ■ राज्य सरकारों, ■ अर्द्धसरकारी विभाग, ■ और अन्य निकाय। ■ स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य और आम जनता या बैंकों को बेचा जा सकता है। • जब भी धन की आवश्यकता होती है (12 महीने से अधिक के लिए जारी नहीं) सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं।
वाणिज्यिक बिल बाजार	<ul style="list-style-type: none"> • व्यवसाय में फर्म द्वारा ये प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। • लक्ष्य: खरीदार को भुगतान में देरी होने पर विक्रेता को क्षतिपूर्ति करना। • चालान पर छूट की दर वसूल की जाने वाली ब्याज दर होती है।
जमा प्रमाणपत्र के लिए बाजार (सीडी)	<ul style="list-style-type: none"> • 1989 में RBI द्वारा जारी किया गया। • किसी बैंक या अन्य संस्था द्वारा जारी किया जाता है जो अल्पकालिक जमा स्वीकार करता है। • सावधि जमा के समान, सिवाय इसके कि उनका अल्पकालिक मुद्रा बाजार में कारोबार किया जा सकता है। • वाणिज्यिक बैंकों को सीडी जारी करने की अनुमति नहीं है। • केवल 6 वित्तीय संस्थान - आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, एक्जिम और भारतीय पुनर्निर्माण बैंक।

वाणिज्यिक पत्रों के लिए बाजार (CPs)	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 में भारत में जारी किया गया। • CP एक उपकरण है जिसका उपयोग निगमों द्वारा अल्पकालिक नकदी जुटाने के लिए किया जाता है। • कार्यशील पूंजी में कम से कम 5 करोड़ रुपये वाला एक सूचीबद्ध व्यवसाय सीपी जारी कर सकता है। • अन्य आवश्यकताओं में हर 6 महीने में CRISIL P2 या ICRA A2 रेटिंग शामिल है।
रेपो बाजार	<ul style="list-style-type: none"> • एक मुद्रा बाजार साधन। • धारक एक निवेशक को प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित गति से पुनर्खरीद करने की प्रतिबद्धता के साथ बेचते हैं। • प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो लेनदेन में एक पूर्व निर्धारित दर पर पुनर्विक्रय करने के वादे के साथ खरीदा जाता है। • रेपो बाजार के उपकरण <ul style="list-style-type: none"> ○ सरकारी प्रतिभूतियां, ○ राजकोषीय चालान, ○ राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, ○ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड ○ निजी कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां।
मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड (MMMFs)	<ul style="list-style-type: none"> • म्यूचुअल फंड के समान लेकिन अल्पावधि हेतु। • 1992 में आरबीआई द्वारा जारी किया गया। • बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र के संस्थान: MMMF स्थापित करने की अनुमति।
डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया (DFHI)	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 में आरबीआई द्वारा स्थापित। • मुद्रा बाजार का विकास और मुद्रा बाजार लिखतों के लिए चलनिधि की व्यवस्था।

असंगठित क्षेत्र



साहूकार	<ul style="list-style-type: none"> • भारत के सबसे स्थानीय मुद्रा बाजार का गठन करते हैं और सबसे अधिक शोषणकारी तरीके से संचालित करते हैं। • संपार्श्विक के साथ व्यक्ति-से-व्यक्ति ऋण देते हैं।
अनियमित गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ	<ul style="list-style-type: none"> • संगठन: हालांकि यह बैंक से संबंधित वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसमें बैंकिंग लाइसेंसिंग का अभाव है। • चिट फंड : <ul style="list-style-type: none"> ○ लोकप्रिय प्रकार के बचत संस्थान। ○ किशतों में समय के साथ एक निर्दिष्ट राशि का योगदान करने के लिए सहमत लोगों के समूह को संदर्भित करता है।

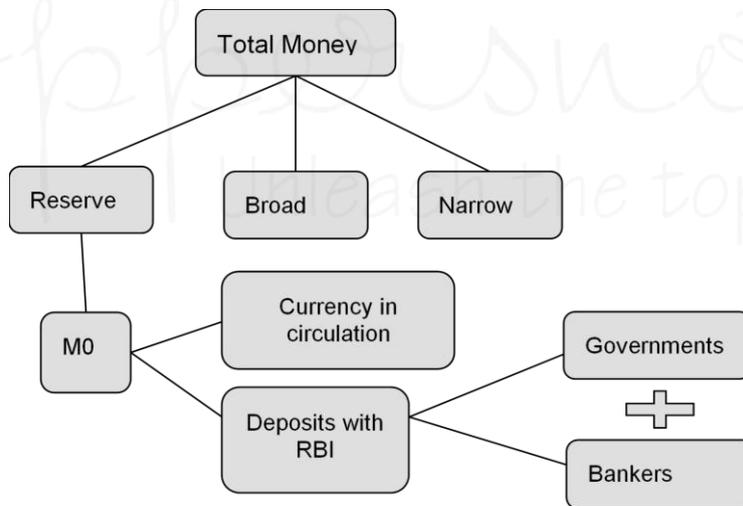
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1982 के चिट फंड अधिनियम के तहत, राज्य सरकार अलग से धन का प्रबंधन, संचालन और विनियमन करती है। ● निधि कंपनियाँ: <ul style="list-style-type: none"> ○ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित। ○ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक वर्ग, आरबीआई उनके लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। ○ केवल अपने शेयरधारक-सदस्यों के साथ व्यवहार करता है। ○ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के मुख्य प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।
--	--

पैसे की आपूर्ति

- किसी दी गई अर्थव्यवस्था में किसी भी समय प्रचलन में धन की मात्रा।
- स्टेट ट्रेजरी, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंकों को छोड़कर, यह लोगों द्वारा रखे गए धन का कुल स्टॉक है, जिसमें व्यक्ति, व्यवसाय, सरकार और इसके घटक निकाय निहित हैं।
- किसी देश द्वारा जारी और अपनाए गए नोटों की प्रणाली उस देश में उपलब्ध धन की मात्रा निर्धारित करती है।
 - उदाहरण के लिए, भारत ने 1957 में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया।
 - भारतीय रिजर्व बैंक : 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम भंडार बनाए रखने के लिए जिसमें शामिल हैं:
 - सोना (सोने का मूल्य 115 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए)।
 - विदेशी प्रतिभूतियां।



नोट: बैंक धन को द्वितीयक धन माना जाता है जबकि नकद धन को उच्च शक्ति वाला धन माना जाता है।



धन गुणक

- यह गणना करता है कि बैंक अपने भंडार के रूप में बनाए गए धन की प्रत्येक इकाई के लिए जमा के रूप में कितना धन बना सकते हैं।



$$\text{धन गुणक} = \frac{\text{व्यापक धन (M3)}}{\text{आरक्षित धन (M0)}}$$

- जब आरक्षित मुद्रा बढ़ती है, तो व्यापक मुद्रा उसके साथ बढ़ती है।
- यह बताता है कि कैसे एक छोटी सी प्रारंभिक जमा धन आपूर्ति में एक बड़ी समग्र वृद्धि की ओर ले जाती है।
- यह दर्शाता है कि जमा की मात्रा में परिवर्तन किस हद तक मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है।

मौद्रिक समुच्चय

- **M1** = जनता के पास मुद्रा + वाणिज्यिक बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट + RBI के पास अन्य जमा।
- **M2** = M1 + डाकघर बचत बैंक जमा।
- **M3** = M1 + वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा।
- **M4** = M3 + कुल डाकघर जमा (NSC को छोड़कर)



- संकीर्ण धन (एम1) = जनता के पास मुद्रा + बैंकों में जनता की मांग जमा
- जब एक तीसरा घटक यानी डाकघर बचत जमा भी M1 में जोड़ा जाता है, तो यह M2 बन जाता है।
- ब्रॉड मनी (M3) = M1 + बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा।

